सुशासन

अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान, भोपाल

Atal Bihari Vajpayee Institute of Public Administration, Bhopal

वार्षिक प्रतिवेदन

(01 अप्रैल 2013 – 31 मार्च 2014)

Annual Report

(1st April 2013 – 31st March 2014)

अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान

(मध्यप्रदेश शासन की स्वशासी संस्थान)

सुशासन भवन, भदभदा चौराहा, टी.टी. नगर, भोपाल–462003

फोन नं– 0755–2777316, 2777318, 2770538

वेबसाइट: **www.aiggpa.mp.gov.in**, ईमेलः **aiggpa@mp.gov.in**

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013–14
विषय–सूची

स.क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	**अध्याय – एक** **संस्थान संबंधी सामान्य जानकारी**	
	1.1 संस्थान की स्थापना	1
	1.2 संस्थान के मुख्य उद्देश्य	1
	1.3 संस्थान की अवधारणा (Vision)	2
	1.4 संस्थान के ध्येय (Mission)	2
	1.5 संस्थान की कार्यप्रणाली	3
	1.6 संस्थान के कार्य स्तंभ	3
	1.7 संस्थान के कार्यक्षेत्र की दिशाएँ	3
	1.8 संस्थान के संकल्प	4
2	**अध्याय – दो** **वर्ष 2013–14 की मुख्य गतिविधियॉं**	
	2.1 इन्टर्नशिप कार्यक्रम	5
	2.2 एकीकृत परिपेक्ष्य योजना एवं वार्षिक योजना बनाने हेतु तकनीकी सहायता संस्था के रूप में कार्य	6
	2.3 ''आइडियाज़ फॉर सीएम'' बेवपोर्टल	7
	2.4 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा SGSY अंतर्गत मध्यप्रदेश के पिछड़े जिलों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की विशेष परियोजना की मानिटरिंग एवं समन्वय	7
	2.5 शासकीय नीति/कार्यक्रमों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव का आंकलन	8–14
	2.5.1 लाडली लक्ष्मी योजना का प्रभाव आंकलन अध्ययन	9
	2.5.2 तेजस्वनी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का प्रभाव आंकलन अध्ययन	9
	2.5.3 दीन दयाल अन्त्योदय उपचार योजना का प्रभाव आंकलन अध्ययन	9
	2.5.4 स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का प्रभाव आंकलन अध्ययन	10
	2.5.5 राष्ट्रीय हरित कोर ''ईको क्लब'' गतिविधियो का प्रभाव आंकलन अध्ययन	10

	2.5.6 वर्चुअल क्लास कार्यक्रम का प्रभाव आंकलन अध्ययन	11
	2.6 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अर्न्तगत थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग एवं एवाल्यूशन	12
	2.7 मध्यप्रदेश में स्थापित लोक सेवा केंद्रो का सर्वेक्षण कार्य	12
	2.8 मध्यप्रदेश दृष्टिपत्र–2018 के बिन्दु क्रमांक 16.5.2 पर कार्यवाही	13
3	**अध्याय – तीन** **सेमीनार/कार्यशालाऐं**	
	3.1 ''परिवर्तन की पहल'' विषय पर कार्यशाला का आयोजन	15
4	**अध्याय – चार** **वित्तीय प्रतिवेदन**	16
5	**अध्याय – पाँच** **नवीन नियुक्तियॉ**	
	5.1 संस्थान के सहायक ग्रेड–1 के पद पर नियुक्ति	17
	5.2 संस्थान में रिसर्च एसोसिएटस् का चयन	17
	5.3 संस्थान में ऑनरेरी रिसर्च एसोसिएटस् का चयन	18
6	**अध्याय – छः** **कोर स्टॉफ द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में सहयोग**	19
7	**अध्याय – सात** **संस्थान की गवर्निंग बॉडी एवं एक्जीक्यूटिव बॉडी**	
	7.1 संस्थान की गवर्निंग बॉडी	20
	7.2 संस्थान की एक्जिक्यूटिव बॉडी	21
8	**परिशिष्ट–1** **इन्टर्नशिप कार्यक्रम 2013–14**	22–24

अध्याय– एक
संस्थान संबंधी सामान्य जानकारी

1.1 संस्थान की स्थापना–

मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग के आदेश क्रमांक एफ/6–3/2011/61/लोसेप्र दिनांक 13.12.2011 द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी। संस्थान का दिनांक 20.01.2012 को मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन पंजीयन किया गया है। संस्थान के अस्तित्व मे आने के बाद ''सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल'' का विघटन कर उसकी समस्त अस्तियां एवं दायित्व इस संस्थान में समाहित किये जाने है।

1.2 संस्थान के मुख्य उद्देश्य–

(i) सुशासन के क्षेत्र में वैश्विक एवं स्थानीय (Global Local) परिप्रेक्ष्य में ''थिंक टैंक'' के रूप में कार्य करना। शासकीय नीतियों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव का आंकलन करना।

(ii) लोक प्रशासन के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करना, समस्याओं को चिन्हित कर उनका समाधान सुझाना, कार्य योजना बनाना तथा उन्हें क्रियान्वित करने में सहायता करना।

(iii) उत्कृष्ट कार्य एवं विधियों तथा ई–प्रशासन के कार्यक्रमों का संकलन कर उनका विस्तारण करना।

(iv) प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार एवं उनके स्वरूप में आवश्यक परिवर्तन संबंधी परामर्श देना।

(v) लोक प्रशासन के ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित करना, जिनमें परिवर्तन एवं सुधार से प्रशासनिक परिणामों तथा उपलब्धियों पर अधिकतम सकारात्मक प्रभाव पड़ता हो।

(vi) प्रशासन को जन–केन्द्रित बनाने के लिये स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा हितबद्ध समूहों के लिये मंच उपलब्ध कराना।

(vii) स्थानीय निकाओं, राज्यों, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं के लिये कार्यक्रमों की संरचना एवं संचालन, एक्शन रिसर्च एवं प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमों के लिये तकनीकी परामर्श एवं सेवायें उपलब्ध कराना।

(viii) लोक सेवा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन।

(ix) स्वैच्छिक संगठन की क्षमता विकसित करने के उपाय।

(x) गवर्निंग बॉडी के द्वारा निर्धारित कोई ऐसा कार्य जो उपरोक्त उद्देश्यों से कवर नहीं होता हो।

1.3 संस्थान की अवधारणा (Vision)–

"सुशासन जो सबको समान अवसर प्रदान करे एवं जिसका लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना हो।"

("Equal opportunity to all through Good Governance geared to improve the quality of lives of our People").

1.4 संस्थान के ध्येय (Mission) –

"Knowledge Resource Hub और Repository के निर्माण एवं अन्य माध्यमों द्वारा सुशासन के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन के विकास का प्रयास, सुनिश्चित करना, जिससे शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जनकल्याण केन्द्रित तथा जिम्मेदार और सुदृढ़ बनाया जा सके" ।

("Develop Knowledge Resource Hub and Repository and other strategies, to motivate and encourage strengthening of Good Governance which is more transparent, participative, accountable and focused on improving the quality of lives of our people").

1.5 संस्थान की कार्यप्रणाली –

संस्थान स्वशासी संस्था के रूप मे संचालित है। संस्थान के शासी निकाय के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्रीजी एवं कार्यकारी निकाय के अध्यक्ष संस्थान के महानिदेशक है। संस्थान की गतिविधियां महानिदेशक, संचालक, कार्यक्रम समन्वयक (Programme Coordinators)/परियोजना अधिकारी (Project Officers)/रिसर्च एसोसियटस (Research Associates)/रिसर्च फैलो (Research Fellows), तथा प्रशासनिक स्टाफ के सहयोग से संचालित होती है। परियोजनाओं से संबंधित विशिष्ट परामर्शदायी विशेषज्ञ/सलाहकार (Distinguished Specialists/Advisors), विशिष्ट फेलो/कन्सलटेंट (Distinguished Fellows/Consultants) संस्थागत/एक्सचेंज कार्यक्रम फेलों (Institutional Fellows, Exchange Programme Fellows) तथा कार्यक्षेत्र अनुभवी विशेषज्ञ (Experts with Field Experience) से भी सहयोग लिया जाता है।

1.6 संस्थान के कार्य स्तंभ –

- शोध, नीति विश्लेषण एवं विकास
- सुशासन के लिए क्षमता विकास को प्रोत्साहन
- प्रबंधन तकनीकियों का सुशासन के लिये उपयोग

1.7 संस्थान के कार्यक्षेत्र की दिशाएँ –

- शासन में नवाचार
- सेवाओं में सुधार और *grassroots* तक विस्तार
- शासन का विकेन्द्रीकरण
- अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास
- शासन में आम समाज की साझेदारी
- ई–शासन
- सुशासन के लिए knowledge hub और repository का निर्माण

- समान उद्देश्यों वाली अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग एवं समन्वय की स्थापना
- सुशासन को प्रोत्साहन

1.8 संस्थान के संकल्प –

- सुशासन संबंधी नीतियों के पालन में शासन को सहयोग प्रदान करने के लिए संस्थान संकल्पित है।
- संस्थान विभिन्न विभागों, संस्थाओं एवं विशेषज्ञों के साथ मिलकर सुशासन स्थापित करने को प्रोत्साहित करेगा।
- आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के प्रयासों में संस्थान सहयोगी होगा।

––00––

अध्याय– दो
वर्ष 2013–14 की मुख्य गतिविधियॉ

2.1 इन्टर्नशिप कार्यक्रम–

शासन तंत्र से आई.आई.एम, आई.आई.टी., ज़ेवियर इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एवं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जैसे राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त संस्थानों के प्रबंधन प्रशिक्षाणार्थियों को जोड़ने हेतु वर्ष 2009 से इंटर्नशिप व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिवर्ष इन्टर्नस् का चयन उपरोक्त संस्थानों के एम.बी.ए. द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों में से किया जाता है। चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार संचालित होती है–

- इन्टर्नशिप व्यवस्था की जानकारी प्रतिवर्ष माह सितम्बर में सभी विभागों को प्रेषित करते हुए आगामी वर्ष मे अप्रैल से जुलाई के अंतराल में अध्ययन हेतु योजनाओ संबंधी प्रस्ताव प्राप्त किये जाते है।
- संस्थान की वेबसाईट पर प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर इच्छुक इंटर्न द्वारा अपनी संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन संस्थान को प्रेषित किये जाते है।
- इंटर्न की योग्यता और रूचि को ध्यान में रखते हुये संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी तथा संस्थान के कोर स्टाफ द्वारा प्राथमिक रूप से चुने गये आवेदकों का वीडियोकांफ्रेंस/टेलीफोन के माध्यम से साक्षात्कार के पश्चात् चयन किया जाता है।
- शासकीय विभागों द्वारा चिन्हित नीतियों/कार्यक्रमों/योजनाओं के अध्ययन के लिये इंटर्न की मेन्टरिंग और अध्ययन हेतु समन्वय का कार्य संस्थान के कोर स्टाफ द्वारा किया जाता है।
- प्रत्येक इंटर्न द्वारा अध्ययन उपरांत अपने सुझाव एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किये जाते है।

वर्ष 2013–14 के लिए में इन्टर्नशिप कार्यक्रम अंतर्गत देश की विभिन्न ख्याति प्राप्त संस्थाओं से 200 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें से कुल 22 आवेदकों का चयन किया गया है। चयनित इंटर्नस् द्वारा भोपाल विकास प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, म.प्र. विद्युत नियमक आयोग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से संबंधित विषयों पर अध्ययन कार्य किया जाएगा। चयनित इंर्टस एवं उनके द्वारा किए गए प्रोजेक्ट का विवरण **परिशिष्ट–1** पर उपलब्ध है।

वर्ष 2014–15 के लिए इन्टर्नशिप कार्यक्रम अंर्तगत 6 इन्टर्नस् का चयन किया गया। चयनित इंटर्नस् आई.आई.टी–कानपुर, आई.आई.टी–रूड़की, आई.आई.टी–मद्रास एवं एन.ए.ए.आर.एम–हैदराबाद के छात्र थे। चयनित इन्टर्नस द्वारा जल संसाधन विभाग, एकीकृत बाल विकास योजना तथा मध्यप्रदेश ग्रह एवं अद्योसंरचना निर्माण बोर्ड से संबंधित विषयों पर अध्ययन कार्य वर्ष 2015–16 मे किया जाएगा।

2.2 एकीकृत परिपेक्ष्य योजना एवं वार्षिक योजना बनाने हेतु तकनीकी सहायता संस्था के रूप में कार्य–

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बी.आर.जी.एफ योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश के पिछड़े जिलों की एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना एवं वार्षिक योजना तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता संस्थाओं के चयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्ताव मांगे गये थे। मध्यप्रदेश के 06 जिलों (अनूपपुर, दमोह, डिण्डोरी, कटनी, सिवनी एवं शहडोल) की एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना एवं वार्षिक योजना बनाने हेतु संस्थान का तकनीकी सहायता संस्था के रूप में चयन किया गया है।

संस्थान द्वारा एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना एवं वार्षिक योजना तैयार करने के लिए उपरोक्त सभी **06** जिलों के सभी विकासखण्डों के पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से योजना तैयार करने के संबंध में चर्चा की गई एवं संबंधित विकासखण्ड की प्रमुख प्राथमिकतायें चिन्हित करते हुए उपरोक्त सभी जिलों की वर्ष 2014–15 की वार्षिक योजना तैयार कर जिला योजना समिति के अनुमोदन हेतु संबंधित जिला पंचायतों को प्रेषित की जा चुकी हैं।

2.3 "आइडियाज़ फॉर सीएम" बेवपोर्टल–

संस्थान द्वारा आम नागरिकों को प्रदेश के विकास से जोड़ने हेतु एवं विकास हेतु आम नागरिकों के सुझाव प्राप्त करने हेतु "आइडियाज़ फॉर सीएम" पोर्टल जनवरी 2009 से संधारित किया जा रहा है। पोर्टल पर पर प्राप्त आईडियाज के विश्लेषण एवं अनुश्रवण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन है। नागरिकों द्वारा किसी आईडिया को प्रेषित करते ही उन्हें ई–मेल के माध्यम से आईडिया प्राप्त होने की सूचना दी जाती है। आईडिया की प्रारंभिक छानबीन के उपरांत यदि आईडिया अग्रिम विश्लेषण हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो उस आईडिया को पंजीकृत कर संबंधित विभाग को अभिमत हेतु ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है। साथ ही सुझावकर्ता को भी ई–मेल के माध्यम से उसके सुझाव के पंजीयन की सूचना देते हुए एक आई.डी. एवं पासवर्ड दिया जाता है, जिसके माध्यम से सुझावकर्ता उनके आईडिया पर समय–समय पर की गई कार्यवाही की स्थित जान सकते है। यदि प्रारंभिक छानबीन के उपरांत आईडिया अग्रिम विश्लेषण हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उस स्थित में भी सुझावकर्ता को ई–मेल के माध्यम से सूचना दी जाती है। पंजीकृत आईडिया पर विभाग का अभिमत प्राप्त होने के उपरान्त पुनः आईडिया का परीक्षण एक समिति द्वारा किया जाता है। तदोपरान्त आईडिया के क्रियान्वयन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में निर्णय लिया जाता है। इस निर्णय के संबंध में भी सुझावकर्ता को ई–मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है।

इस बेवसाईट को www.ideasforcm.in पर देखा जा सकता है। वर्ष 2013–14 के दौरान इस वेबसाईट के माध्यम से 237 आईडियाज़ प्राप्त हुए हैं, जिनमे से प्रारंभिक तौर पर चयनित 13 आईडिया संबंधित विभागो के अभिमत हेतु प्रेषित किए गए है।

2.4 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा SGSY अंतर्गत मध्यप्रदेश के पिछड़े जिलों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की विशेष परियोजना की मानिटरिंग एवं समन्वय–

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाय.) अंतर्गत मध्यप्रदेश के 12 पिछड़े जिलों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे 10,000 बेरोजगार युवक/युवतियों को सघन प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार दिये जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की विशेष परियोजना स्वीकृत की गई। योजना की कुल लागत राशि रू. 1,496.00 लाख है, जिसमें केन्द्रांश राशि रू. 1,122.00 लाख एवं राज्यांश राशि रू. 374.00 लाख है। परियोजना की अवधि दो वर्ष है एवं परियोजना अवधि में 12 जिलों के 10,000 युवाओं/युवतियों को 8 ट्रेड में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाना है। योजना का क्रियान्वयन "क्रिस्प" (**Centre for Research and Industrial Staff Performance, Bhopal**) द्वारा किया जा रहा है। परियोजना अंतर्गत 08 ट्रेड– 1. रेडीमेड गारमेंट मेकिग, 2. सेल्स एवं मार्केटिग, 3. सिक्योरिटी सर्विस, 4. कम्प्यूटर हार्डवेयर रिपेयर एवं मेन्टेनेन्स, 5. बेसिक इलेक्ट्रिशियन, 6. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, 7. मशीन मेकेनिक एवं 8. हेण्डीक्राफ्ट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

क्रियान्वन संस्था द्वारा मार्च 2014 तक योजना अर्न्तगत 10,000 हितग्राहियो के प्रशिक्षण लक्ष्य के विरूद्ध 10,014 हितग्राहीयों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा 7,500 के लक्ष्य के विरूद्ध 7,682 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। संस्थान द्वारा परियोजना का अनुश्रवण एवं समन्वय किया गया। परियोजना की सफल मॉनिटरिंग एवं समन्वय किये जाने एवं आवश्यक सहयोग तथा मार्गदर्शन दिये जाने से परियोजना को सफल क्रियान्वयन के लिए दो राष्ट्रीय पुरस्कार (**Quality Council of India and DL Shah Trust, New Delhi**) प्राप्त हुए।

2.5 शासकीय नीति/कार्यक्रमों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव का आंकलन–

संस्थान का एक मुख्य उद्देश्य शासकीय नीतियों/कार्यक्रमों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव के आंकलन करना है। इसी कड़ी मे संस्थान द्वारा निम्नलिखित योजनाओ के प्रभाव आंकलन का कार्य प्रांरम्भ किया गया है:–

2.5.1 लाडली लक्ष्मी योजना का प्रभाव आंकलन अध्ययन–

कार्यकारी निकाय के निर्देशों के परिपालन में योजना का अध्ययन संस्थान के स्वयं के वित्तीय स्त्रोतों से प्रारंभ किया गया था। अध्ययन हेतु प्रदेश के 6 जिलों की 18 परियोजनाएं चयनित की गईं है। तीन प्रकार के उत्तरदाताओं– 1934 हितग्राही, 1303 नवविवाहिता एवं किशोरी बालिकाएं तथा 91 पात्र किन्तु लाभ नहीं लिया कुल 3,328 उत्तरदाताओं को अध्ययन में शामिल किया गया है। संस्थान द्वारा लाभार्थियो से आंकड़ो के संग्रहण हेतु तीन अलग–अलग प्रश्नावालियों का निर्माण कर क्षेत्र अन्वेषको के माध्यम से आंकड़ो का संग्रहण पूर्ण किया गया है। आंकड़ों का विश्लेषण कर जून 2014 तक प्रतिवेदन संबंधित विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

2.5.2 तेजस्वनी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का प्रभाव आंकलन अध्ययन–

संस्थान द्वारा महिला वित्त एवं विकास निगम के अनुरोध पर महिला सशक्तिकरण संचालनालय द्वारा संचालित एवं ''अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष'' द्वारा वित्त पोषित ''तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम'' का प्रभाव आंकलन अध्ययन तीन जिलों में प्रारंभ किया गया है। तीन जिलों में 15 लोकेशन केन्द्र के 300 समूहों के 1191 समूह सदस्यों, 586 समूह पदाधिकारियों एवं 58 सामुदायिक संगठकों, इस प्रकार कुल 1835 उत्तरदाताओं को अध्ययन में शामिल किया गया। संस्थान द्वारा विभिन्न हितग्राहियो से आंकड़ो के संग्रहण हेतु अलग–अलग प्रश्नावालियों का निर्माण कर क्षेत्र अन्वेषको के माध्यम से आंकड़ो का संग्रहण पूर्ण कर लिया गया है। आंकड़ों का विश्लेषण कर जून 2014 तक प्रतिवेदन संबंधित विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

2.5.3 दीन दयाल अन्त्योदय उपचार योजना का प्रभाव आंकलन अध्ययन–

कार्यकारी निकाय के निर्देशों के परिपालन में संस्थान द्वारा इस योजना का अध्ययन संस्थान के स्वयं के वित्तीय स्त्रोतों से प्रारंभ किया गया है। अध्ययन हेतु प्रत्येक राजस्व संभाग से रेन्डम आधार पर एक जिले का चयन किया गया है। प्रत्येक जिले से बी.पी.एल. जनसंख्या के आधार पर दो विकासखंडो को अध्ययन हेतु चयनित करते हुए प्रत्येक विकासखंड से आठ ग्रामो का चयन किया गया है। अध्ययन हेतु चयनित प्रत्येक ग्राम से छः लाभार्थी परिवारों का चयन कर प्रश्नावली के माध्यम से

आंकड़ों का सग्रहण किया गया है। इस प्रकार 10 जिले नामतः– सतना, सागर, इन्दौर, देवास, ग्वालियर, मुरैना, डिन्डौरी, जबलपुर, सिहोर एवं बैतूल तथा 20 विकासखंड, 160 ग्राम एवं 960 लाभार्थी परिवारों एवं प्रत्येक चयनित जिले तथा विकासखण्ड के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ एवं अधिकारी एवं विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारियों को अध्ययन में शामिल किया गया है। संस्थान द्वारा विभिन्न हितधारकों से आंकड़ो के संग्रहण हेतु अलग–अलग प्रश्नावालियों का निर्माण किया गया। संस्थान द्वारा आंकड़ों का संग्रहरण पूर्ण कर लिया गया है। आंकड़ों का विश्लेषण कर जून 2014 तक प्रतिवेदन संबंधित विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

2.5.4 स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का प्रभाव आंकलन अध्ययन–

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारो का आर्थिक स्तर सुधारने एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से मध्यप्रदेश में स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना की विशेष परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। भारत शासन के ग्रामीण विकास विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वित्तीय सहयोग से मध्यप्रदेश में योजना की क्रियान्वयन संस्था ''सेंटर फॉर रिसर्च एंड इण्डस्ट्रियल स्टॉफ परफॉरमेन्स (क्रिस्प), भोपाल'' है। क्रियान्वित एजेन्सी द्वारा 12 जिलो से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 10,000 युवाओं को आवश्यक कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराकर जीवन स्तर को ऊपर उठाना उद्देश्य है। संस्थान द्वारा विभिन्न हितधारकों से उद्देश्य के संबंध में आंकड़ो के संग्रहण हेतु **चार** अलग–अलग प्रश्नावालियों का निर्माण– प्रशिक्षणार्थियो के लिये, योजनांतर्गत रोजगार प्राप्त हितग्राही के लिये, योजनांतर्गत रोजगार छोड़ चुके हितग्राही के लिये तथा रोजगार प्रदाता उद्योग के लिये किया गया है। संस्थान द्वारा आंकड़ो के संग्रहण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आंकड़ों का विश्लेषण कर जून 2014 तक प्रतिवेदन संबंधित विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

2.5.5 राष्ट्रीय हरित कोर ''ईको क्लब'' गतिविधियो का प्रभाव आंकलन अध्ययन–

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) द्वारा संचालित एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय हरित कोर योजना अंतर्गत ''ईको क्लब'' गतिविधियों के आंकलन का कार्य एप्को द्वारा संस्थान को सौपा गया है।

संस्थान द्वारा अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के छः जिले नामतः धार, अनूपपुर, मण्डला, शिवपुरी, सिहोर एवं छतरपुर जिले का चयन किया गया। अध्ययन हेतु शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के कुल 156 स्कूलों के प्राचार्य तथा ईको क्लब प्रभारी शिक्षकों के साथ प्रत्येक चयनित जिले के मास्टर ट्रेनर्स एवं सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास)/जिला शिक्षा अधिकारियों को चयनित किया गया। संस्थान द्वारा लक्षित हेतु हितधारकों से योजना के संबध मे उनकी राय एवं अपेक्षाए जानने तथा योजना प्रभाव के आंकलन हेतु पांच विस्तृत प्रश्नावलियों निर्मित कर आंकड़ों का संग्रहरण किया गया है। आंकड़ों का विश्लेषण जून 2014 तक पूर्ण कर प्रतिवेदन संबंधित विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

2.5.6 वर्चुअल क्लास कार्यक्रम का प्रभाव आंकलन अध्ययन–

प्रदेश में शिक्षा के लोकव्यापीकरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में यह परियोजना क्रियान्वित है। यह परियोजना प्रदेश के 313 विकासखंड मुख्यालयों (89 आदिवासी विकासखण्ड तथा 224 सामान्य विकासखण्ड) में यथास्थिति स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा चिन्हित 01 शासकीय उत्कृष्ट/सामान्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इस प्रकार कुल 313 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 से कक्षा 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लागू है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शिक्षा के लोकव्यापीकरण एवं दूरस्थ अंचलों तक गुणवत्ता एवं अबाधित शिक्षा सुलभ कराने के उद्धेश्य से सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग कर शासकीय महाविद्यालयों एवं शासकीय विद्यालयों में वर्चुअल/स्मार्ट कक्षाओं का संचालन प्रारम्भ किया गया। इस परियोजना की क्रियान्वन एजेंसी मैप आई.टी. (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) द्वारा इस परियोजना के अध्ययन का कार्य संस्थान को सौंपा गया है। अध्ययन हेतु संस्थान द्वारा चेक लिस्ट एवं चार साक्षात्कार अनुसूची को तैयार किया गया– विद्यार्थी हेतु, व्याख्याता/प्राचार्य हेतु, जिला ई–गवर्नेंस मेनेजर/असिसटेंट ई–गवर्नेंस मेनेजर हेतु, मास्टर ट्रेनर/ई–व्याख्याता (विशेषज्ञ शिक्षक)/टेली टीचर हेतु। इन साक्षात्कार अनुसूची को क्रियान्वन संस्था के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है। मेप आई.टी से

अनुसूची का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत आकंड़ों के संग्रहण का कार्य संस्थान द्वारा वर्ष 2014–15 मे किया जायेगा।

2.6 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अर्न्तगत थर्ड पार्टी मोनिटरिंग एवं एवाल्यूशन–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग एवं एवाल्यूशन का कार्य किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा संस्थान को सौपा गया है। संस्थान द्वारा विभाग से चर्चा कर अध्ययन हेतु छः जिलो (देवास, रायसेन, कटनी, शहडोल, धार एवं हरदा) का चयन किया गया। संस्थान द्वारा अध्ययन के लिए प्रश्नावली का निर्माण कर क्षेत्र अन्वेषको के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण किया गया है। आंकड़ों का विश्लेषण जून 2014 तक पूर्ण कर प्रतिवेदन संबंधित विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

2.7 मध्यप्रदेश में स्थापित लोक सेवा केंद्रो का सर्वेक्षण कार्य–

''मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010'' नागरिक अधिकारों को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य शासन का उल्लेखनीय कदम है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित एवं जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा अधिसूचित सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड एवं नगरीय क्षेत्रों में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप में 336 लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है। मध्यप्रदेश के समस्त जिलों के विकासखंड एवं नगरीय क्षेत्रों में लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना हुये 2 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। इन लोक सेवा केन्द्रों के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता के प्रभाव आंकलन हेतु म.प्र. राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा संस्थान को लोक सेवा केंद्रो के सर्वेक्षण का कार्य सौपा गया। संस्थान द्वारा इस कार्य हेतु राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित चार सर्वेक्षण संस्थाओं को चिन्हित किया गयाः–

1. समर्थन, भोपाल,
2. सेंटर फॉर रिसर्च प्लानिंग एंड एक्शन, नई दिल्ली,
3. गायत्री रूरल एजुकेशन सोसायटी, श्रीकाकुलम, आंध्रप्रदेश एवं
4. विमर्श, गुड़गांव, हरियाणा।

मध्यप्रदेश के सभी जिलों में पी.पी.पी. मोड के तहत स्थापित लोक सेवा केन्द्र सुचारू रूप से कार्य कर रहे है अथवा नहीं एवं उनके द्वारा आर.एफ.पी. में दिये गये मापदण्ड के अनुसार कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं, सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोक सेवा केन्द्रों के कार्य करने का निष्पक्ष निरंतर फीड–बैक लिये जाने के लिये भी सर्वेक्षण की आवश्यकता है। सर्वेक्षण के प्रथम चरण मे 56 लोक सेवा केन्द्रों का सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है। सर्वेक्षण मे मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दु शामिल किये गये है :–

1. लोक सेवा केन्द्रों में हार्डवेयर, स्वान, ब्राडबैंड कनेक्टिविटी, नागरिक सुविधाओं, मानव संसाधन की उपलब्धता एवं उनके लाभार्थियों के प्रति व्यवहार की जानकारी।
2. विभिन्न लोक सेवाओं के लिये केन्द्र द्वारा लिये जा रहे शुल्क एवं उसकी प्रक्रिया की जानकारी।
3. जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की उनके क्षेत्र मे स्थापित लोक सेवा केन्द्र की सेवा के प्रति संतुष्टि का स्तर।
4. लोक सेवा केन्द्रों के संचालन में आ रही समस्याओं एवं निराकरण हेतु सुझाव/राय ज्ञात करना।

सर्वेक्षण अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिये चार प्रश्नावलियों का निर्माण किया गया है:– लोक सेवा केन्द्र के लाभार्थियों के लिए, जनप्रतिनिधियों/आम नागरिकों के लिए, लोक सेवा केन्द्रों के प्रबंधकों के लिए तथा पदाभिहित अधिकारियों के लिए। इन प्रश्नावलियों के माध्यम से सर्वेक्षण संस्थाओं द्वारा विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त की गई है। संस्थान द्वारा सर्वेक्षण संस्थाओं से प्राप्त आंकड़ों का संकलन एंव विश्लेषण किया जा रहा है एवं विश्लेषण उपरांत सर्वेक्षण प्रतिवेदन राज्य लोक सेवा अभिकरण को प्रेषित किया जायेगा।

2.8 मध्यप्रदेश दृष्टिपत्र–2018 के बिन्दु क्रमांक 16.5.2 पर कार्यवाही–

विभागीय अधिनियमों, नीतियों और नियमों के प्रावधनो की अतिरेकता (Redundancy) को पहचानने एवं इनको दूर करने का निर्णय शासन द्वारा मध्यप्रदेश दृष्टिपत्र–2018 के बिन्दु क्रमांक 16.5.2 पर लिया गया।

शासन द्वारा यह कार्य संस्थान को सौंपा गया है। संस्थान द्वारा पत्र दिनांक 08.01.2014 के माध्यम से सभी विभागो को निम्न जानकारी संस्थान को उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है:–

1. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियमों एवं नियमो की सूची,
2. विभागो की महत्वपुर्ण नीतियों की सूची (नीति संबंधी अभिलेख सहित) तथा
3. विभागीय अधिनियामों, नियमों एवं नीतियों में विभाग के मत अनुसार अतिरेकता (Redundancy)

संस्थान द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से भी अनुरोध किया गया कि सभी विभागो को उपरोक्त जानकारी संस्थान को उपलब्ध कराने हेतु यथोचित निर्देश जारी किए जाए।

––00––

अध्याय– तीन
सेमीनार/कार्यशालाऐं

3.1 ''परिवर्तन की पहल'' विषय पर कार्यशाला का आयोजन–

संस्थान द्वारा जिला/जनपद/ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों एवं ग्राम पंचायत के सचिवों हेतु ''परिवर्तन की पहल'' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 04 मई 2013 को भोपाल मे आयोजित किया गया, जिसमे सीहोर एवं भोपाल जिले के 35 जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम पंचायत के सचिवों ने भाग लिया।

कार्यशाला में नवीन एवं रोचक गतिविधियों के माध्यम से सहभागियों को अपने कार्य–व्यवहार के बारे में गहराई से आंकलन करने के अवसर उपलब्ध कराये गये। समाज के विकास में बाधाओं एवं उसे दूर करने हेतु सहभागिता एवं उनकी भूमिका के बारे में सोचने और अपने मन की बात कहने हेतु मंच उपलब्ध कराया गया। दूसरों के प्रति सोच तथा दृष्टिकोण बदलने एवं उस परिपेक्ष्य में स्वयं की जिम्मेदारियों को स्वीकारने का साहस पैदा हो सके इसके लिए छोटे–छोटे वास्तविक उदाहरणों की झलकियाँ (क्लिपिंग) दिखाई गईं, ताकि वे अपने अंदर छिपी कमजोरियों और नकारात्मक बातों को दूर कर अपने अंदर छिपी सकारात्मक सोच और अच्छाइयों से परिचित हो सकें।

––00––

अध्याय– चार
वित्तीय प्रतिवेदन

वर्ष 2013–14 में अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान के लिए रूपये 500.00 लाख का बजट प्रावधान निम्नानुसार प्रस्तावित था –

मद		राशि (लाख में)
001 – अद्योसंरचना अनुदान	–	000
002 – संधारण अनुदान	–	500
योग	**–**	**500**

उपरोक्तानुसार प्रावधानित बजट से संस्थान द्वारा वर्ष 2013–14 में रूपये 125 लाख की राशि आहरित की गई एवं शेष राशि रूपये 375 लाख समर्पित की गई ।

––00––

अध्याय– पाँच
नवीन नियुक्तियॉ

5.1 संस्थान मे सहायक ग्रेड -1 के पद पर नियुक्ति–

संस्थान में सहायक ग्रेड-1 पद के लिए चयन हेतु जनवरी 2013 मे आवेदन आमंत्रित किए गए। आवेदनो की छटनी का कार्य संस्थान द्वारा किया गया। छटनी उपरान्त उम्मीदवारो को चयन प्रक्रिया अंतर्गत लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कर के लिए आंमत्रित किया गया। उक्त पद हेतु निम्नलिखित उम्मीदवार का चयन अप्रैल 2013 में किया गयाः–

स. क्र.	चयनीत उम्मीदवार का नाम	पद नाम
1	श्री श्रीराज नायर	सहायक ग्रेड -1

5.2 संस्थान में रिसर्च एसोसिएटस् का चयन–

संस्थान द्वारा 5 चिन्हित विषयो पर शोध कार्य हेतु रिसर्च एसोसिएटस् का चयन मई–जून 2013 मे किया गया है। चयनित रिसर्च एसोसिएटस् एवं उनके द्वारा किए जा रहे कार्यो का विवरण निम्न अनुसार हैः–

स.क्र.	रिसर्च एसोसिएटस् का नाम	शोध कार्य का विवरण
1	श्री मो. नासिर अहमद	राष्ट्रीय एवं अर्तराष्ट्रीय संस्थानो द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनो का अध्ययन एवं राज्य से संबंधित सुझावों को विभाग की जानकारी मे लाना।
2	श्रीमति सुमन जायसवाल	रिकार्ड डिस्ट्रक्शन नियमों का अध्ययन एवं विस्तृत नये नियमों का निर्माण।
3	श्री विरेन्द्र धाकड़	बेस्ट प्रक्टिसेस का डाक्यूमेंटेशन।
4	सुश्री शैली पाण्डेय	अर्न्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय उत्कृष्ट कार्योविधियों का अध्ययन एवं मध्यप्रदेश में विस्तारण।
5	श्री शरद कुमार आल्हा	रूरल एनर्जी बजट विषय पर अध्ययन हेतु प्रोजेक्ट प्रस्ताव तैयार करना।

इन रिसर्च एसोसिएटस् द्वारा संस्थान के कोर स्टाफ के मार्गदर्शन में उक्त विषयो पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

5.3 संस्थान में आँनरेरी रिसर्च एसोसिएटस् का चयन–

संस्थान द्वारा श्री एल.एस. बघेल, आई.ए.एस. (रिटायर्ड) एवं पूर्व आयुक्त, लोक शिक्षण का चयन दिनांक 12.02.2014 को ''Strengthening of School Governance'' विषय पर ''स्ट्रेटजी पेपर'' तैयार करने के लिये किया गया है। श्री बघेल द्वारा यह कार्य आँनरेरी रिसर्च एसोसिएटस के रूप मे किया जा रहा है। संस्थान द्वारा इस विषय पर कार्य करने के लिये UNICEF से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास भी किया जायेगा।

––00––

अध्याय– छः
कोर स्टॉफ द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में सहयोग

6.1 श्री अखिलेश अर्गल, संचालक आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में ''**सूचना का अधिकार**'' विषय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रिसोर्स पर्सन के रूप में नियमित रूप से अपनी सेवाऐं दी हैं।

6.2 "Awards for Excellance in e-Governance intiatives in the State for the Year 2012-13"– श्री अखिलेश अर्गल, संचालक ने सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग द्वारा दिए जा रहे उपरोक्त पुरस्कारो के चयन की ज्यूरी समिति में सदस्य के रूप मे अपनी सेवाए दी।

6.3 श्री सौरभ बन्सल, कार्यक्रम समन्वयक (ज्ञान प्रंबधन) ने म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में State Project Manager (Information Technology) पद के चयन हेतु गठित साक्षात्कार समिति में विषय विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दी है। साथ ही श्री बंसल द्वारा "Awards for Excellance in e-Governance intiatives in the State for the Year 2012-13" अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लिए प्राप्त प्रस्तावों की छानबीन समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाए दी है।

6.4 श्रीमति ऋचा मिश्रा, कार्यक्रम समन्वयक (सुशासन) ने प्रशासनिक अकादमी द्वारा लोक सेवा केन्द्र प्रबंधकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण में **'लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम एवं लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना'** तथा कॉलेज/विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं लेक्चरर्स के लिए आयोजित ''**प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण**'' विषय पर स्त्रोत व्यक्ति के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की गई है। उन्होने विभिन्न अशासकीय संस्थाओं द्वारा ''**स्व–सहायता समूहों के प्रशिक्षण एवं नगरीय समितियों के प्रशिक्षण**'' हेतु भी स्त्रोत व्यक्ति के रूप में सेवाएं दी है।

––00––

अध्याय– सात
संस्थान की गवर्निंग बॉडी एवं एक्जीक्यूटिव बॉडी

7.1 संस्थान की गवर्निंग बॉडी –

संस्थान की गवर्निंग बॉडी निम्नानुसार है–

क्रमांक	पद नाम	पद
1	माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन	अध्यक्ष
2	माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, वित्त विभाग	सदस्य
3	माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
4	माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग	सदस्य
5	माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	सदस्य
6	माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग	सदस्य
7	मुख्य सचिव, म.प्र. शासन	सदस्य
8	महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, भोपाल	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग	सदस्य
10	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
11	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग	सदस्य
12	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
13	सचिव, म.प्र. शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग	सदस्य
14	प्रोफेसर, ऋषिकेष टी. कृष्णन,, निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान, इन्दौर	सदस्य
15	डॉ जी.ए. किन्हाल, निदेशक, भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल	सदस्य
16	महानिदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान, भोपाल	सदस्य सचिव

7.2 संस्थान की एक्जिक्यूटिव बॉडी –

संस्थान की एक्जिक्यूटिव बॉडी निम्नानुसार है–

क्रमांक	पद नाम	पद
1	महानिदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग	सदस्य
5	गवर्निंग बॉडी की सूची में स.क्र. 15 से 17 में से तीन सदस्य चक्रानुक्रम से	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग	सदस्य
8	राज्य शासन द्वारा नामांकित दो अशासकीय सदस्य	सदस्य
9	संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान	सदस्य सचिव

––00––

परिशिष्ट–1

इन्टर्नशिप कार्यक्रम 2013–14

S. No.	Name of Intern	Name of Institute	Department	Study Topic / Project Assigned
1	Mr. Saif Ahmed	IIT-Kanpur	Bhopal Development Authority (BDA)	Identification of Critical Success Factors and Best Practices for Public Private Partnership Project in Madhya Pradesh
2	Mr. Hiren Nath	IIT-Roorkee	M.P. Electricity Regulatory Commission	Process Mapping for Various services Provided to HT Industrial Consumers against Performance Standards and Suggestions for Improvement.
3	Ms. Ankita Sahare	IIT-Kanpur	Women and Child Development	Impact Assessment of Supplementery Nutritional Services, provided by ICDS
4	Mr. Shrikant	IIT-Roorkee	M.P. Electricity Regulatory Commission	Process Mapping for new LT connections in Urban Area as Against Performance Statdards and Suggestions for Improvements
5	Mr.Ravindra Reddy	IIT- Madras	M.P. Electricity Regulatory Commission	Process Mapping for Various services Provided to HT Industrial Consumers against Performance Standards and Suggestions for Improvement.
6	Mr. Dheer Kapoor	XIM-Bhubaneswar	Bhopal Development Authority (BDA)	Baseline Study and Mapping trends of Urbanization under Aerocity Project
7	Mr. Aditya Kumar	IIT-Madras	M.P.Housing & Infrastructure Board	Economic Feasibility of Housing Projects and Study of IT Interventions and its Benefits

8	Mr. Yogendra Pratap Singh	IIT-Kanpur	M.P.Housing & Infrastructure Board	Critical Factors affecting the Quality Performance in Construction of M.P. Housing and Infrastructure Board
9	Mr. Vikas Kumar Singhal	IIT-Roorkee	M.P. Pollution Control Board	Comparitive Study of E-Waste Management at International Level
10	Mr. Ashwin Siddharth	IIT-Madras	M.P. Pollution Control Board	Measures for Efficient implementation of E-Waste Management in Madhya Pradesh
11	Mr. Arpit Pandey	IIT-Madras	Disaster Management Institute (DMI)	Disaster Management Structure of Bhushan Steel and Power Ltd., Jharkhand
12	Mr. Shashank Shivhare	IIT-Kanpur	Disaster Management Institute (DMI)	Off-Site Emergency Management Plan for Pithampur Industrial Area
13	Mr. Harsh Gupta	IIT-Madras	Environment Planning and Coordination Organization (EPCO) , Bhopal	Analysis of National Green Corps (NGC)
14	Ms. Shivalika Gupta	XIM-Bhubaneswar	Environment Planning and Coordination Organization (EPCO) , Bhopal	Understanding the Perspective of Rural Farming Community in the Upper Catchment of Bhoj Wetland for Developing and Incentive based Mechanism through Community Participation.
15	Mr. Varun Sharma	IIT-Roorkee	State Institute of Town Planning	Analysis of Special Project and Township Rules of Madhya Pradesh
16	Mr. Abhishek Srivastava	IIT-Madras	State Institute of Town Planning	Impact Assessment of Web Based Automated Layout Plan Screening and Approval System
17	Mr. Abhijeet	IIT-Madras	Commissioner, Town and Country Planning	Transit Oriented Development in Bhopal

18	Ms. Anuja Srivastava	IIT-Roorkee	Commissioner, Town and Country Planning	Analysis of Compensation Techniques for Land Acquisition in Different States and Proposing the Appropriate for M.P.
19	Mr. Ashish Nautiyal	NAARM, Hyderabad	PICU, Water Resource Department	Impact Assessment of Karmodia and Dahod Irrigation System under MP Water Sector Restructuring Project
20	Mr. Lokesh Kumar	NAARM, Hyderabad	PICU, Water Resource Department	Impact Assessment of Doraha Irrigation System under MP Water Sector Restructuring Project
21	Mr. Deep H Shah	IIT-Madras	Urban Administration & Development	Competetive Advantage - Million + Cities of M.P.
22	Mr. Chandan A Banait	IIT-Kanpur	Urban Administration & Development	Population Density and Per Capita Expenditure on Basic Services

——00——